



नगर योजना एवं प्रबंधन के लिये स्मार्ट सिटी संकल्पना, रोहतास

दशरथ कुमार¹ | डॉ जयशंकर प्रसाद सिंह²

¹ एम. ए. नेट (भूगोल) वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा,

² विभागध्यक्ष (भूगोल) शेरशाह कॉलेज, सासाराम,

ABSTRACT

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बड़े जोर-शोर से 25/06/2005 को शहरी भारत की तस्वीर को रूपांतरित करने वाली तीन अति महत्वाकांक्षी मिशनों का शुभारंभ किए—

Keywords: (1) स्मार्ट सिटी मिशन (2) सबके लिए आवास मिशन (3) अमृत मिशन

प्रधानमंत्री शहरी विकास मंत्री और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के अन्य कर्ताधर्ता यह दावा कर रहे हैं कि इन तीनों मिशनों को क्रियान्वित करके वे शहरी भारत (31.6%) को एक चमकते दमकते भारत के रूप में रूपांतरित कर देंगे। यह दावा वर्ष 2005-06 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (JNNUM) मिशन के शुभारंभ करते हुए पूर्ववर्ती UPA सरकार द्वारा भी किया गया था। इस मिशन के तहत 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाला (7), 10-40 लाख जनसंख्या वाला (28) राज्यों की राजधानी एवं धार्मिक/ऐतिहासिक तथा पर्यटन महत्व वाले (28), शहरों का चयन किया गया।

स्मार्ट सिटी :- निःसंदेह शहर प्रत्येक शहर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि के इंजन हैं। भारत के लगभग 31% जनसंख्या को समेटें भारत का शहरी क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान देता है। एक आकलन के अनुसार सन् 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या शहरों में रह रहा होगा तथा राष्ट्र के सकल GDP में योगदान बढ़कर 75% होगा।

स्मार्ट सिटी :- परियोजना के तहत देश भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है जिनपर 2015-20 तक पाँच वर्ष में कुल 48000 करोड़ खर्च किया जाएगा। इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी में (24), घण्टे बिजली-पानी की सुविधा के साथ-साथ पूरे शहर में बाई-फाई Connection होगा। प्रति 2500 जनसंख्या पर एक नरसरी स्कूल तो 1.25 लाख की जनसंख्या की जनसंख्या पर एक कॉलेज होगा प्रथम चरण में कुल (20), शहर का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा। जहाँ तक स्मार्ट सिटी को परिभाषित किए जाने का प्रश्न है तो इसकी कोई सर्वभौमिक (न्दपअमर्तस) रूप से स्वीकार्य परिभाषा नहीं है, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा (बुद्धिमत्त) शहर से शहर तथा देश से देश के स्तर पर बदलती रही है। लेकिन इतना तो तय है कि सिटी एक ऐसा शहर हो सकता है, जिससे लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, स्वच्छ वायु में सांस ले सकें। भीड़-भाड़ से मुक्त सड़कों एवं बाजारों से गुजर सकें। त्वरित तथा नीची लागत वाली भौतिक, ज्ञानवान, सम्पर्कता का लाभ उठा सकें।

अध्ययन क्षेत्र -

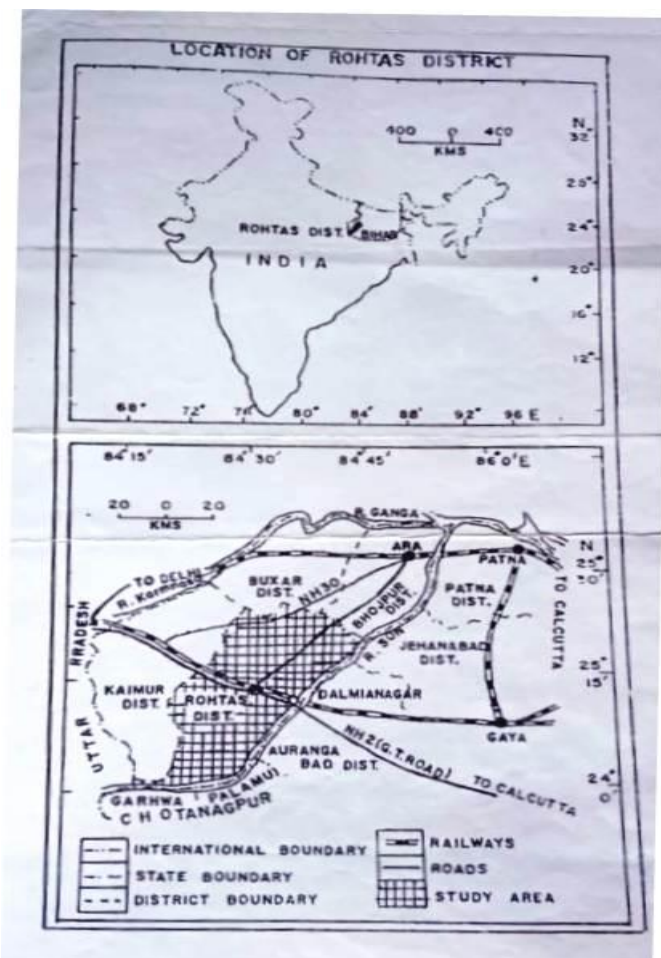
10 नवम्बर 1972 के पुराने शाहाबाद जिला से अलग कर रोहतास जिला का निर्माण किया गया। वर्तमान रोहतास जिला पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्त्व रखता है। पूर्व-दक्षिण में नदी, पश्चिम-दक्षिण में विंध्य पर्वत-श्रृंखला से आवेष्टित इस क्षेत्र के वैदिक काल में करुष क्षेत्र कहा जाता था। इस जिले का चौहदी पूर्व में औरंगाबाद जिला, पश्चिम में कैमूर, उत्तर में भोजपुर एवं बक्सर जिला, दक्षिण में पलामू है। इस जिले का आक्षांशीय विस्तार 24°25' उत्तर तथा देशान्तर्रीय विस्तार 83°45' से लेकर 84°22' पूर्व तक है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 109.7 मीटर है। इस जिले में अनुमंडलों का संख्या 3 प्रखण्ड 19 है। सम्पूर्ण जिले का क्षेत्रफल 3,851 वर्ग कि.मी. है जबकि जनसंख्या 24,50,748 (वर्ष 2011) है। रोहतास जिले में नगरीय जनसंख्या 3,26,806 है। कुल मिलाकर रोहतास जिले में सात शहर हैं जिनमें सासाराम और डेहरी की जनसंख्या 1 लाख से उपर से उपर (1.31 लाख, 1.19 लाख) है। विक्रमगंज की जनसंख्या 35 हजार, नासरीगंज की 25 हजार, नोखा का 26 हजार, कोचस 21597 हजार, क्वाथ का 16 हजार है।

तापक्रम -

औसत तापक्रम 18° से 30° सें.ग्रे. है। अधिकतम 44.3° से.ग्रे. मार्च न्यूनतम ताप 21.3°

से.ग्रे. से दूसरी तरफ ठण्डा महीना अधिकतम 27°5 सें.ग्रे. न्यूनतम 6.8° सें.ग्रे.,

दिसम्बर-जनवरी 3° से 4°से.ग्रे. वार्षिक ताप, 15.5 रोहतास जिले के मैदानी भाग में नदियों के किनारे प्राचीन काल से ही कृषि कार्य की जा रही है। पिछली शताब्दी के पूर्व की कृषि के स्वरूप का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। 1863-68 के पूर्व जिले के किसी भी भाग के कृषि सम्बन्धित न तो आँकड़े उपलब्ध हैं न ही भूमि उपयोग के मानचित्र उपलब्ध है।



स्मार्ट सिटी उसे कहा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित आधारभूत संरचना तत्व मौजूद हो -

- यथोचित स्वच्छ पेयजलापूर्ति,
- सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति

- (iii) ठोस कचरा प्रबंधन सहित स्वच्छता,
- (iv) दक्ष शहरी गत्यात्मक एवं सार्वजनिक परिवहन,
- (v) वहन करने योग्य आवास, निर्धनों के लिए,
- (vi) सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सम्पर्कता एवं डिजिटलीकरण,
- (vii) E- गर्वनेनस एवं नागरिक सहभागिता युक्त शासन
- (viii) सम्पोषणीय पर्यावरण
- (ix) स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था
- (x) नागरिक सुरक्षा विशेषकर बालक एवं महिला के लिए।

- स्मार्ट समाधान :-
- (i) जनसूचना एवं शिकायत निवारण प्रणाली
 - (ii) Electronic सेवा प्रदान करना
 - (iii) नागरिकों की सहभागिता
 - (iv) अपराधों का वीडियो अनुश्रवण
 - (v) कचरा से ऊर्जा एवं इंधन
 - (vi) कचरा से कम्पोस्ट खाद
 - (vii) गन्दे पानी का उपचार
 - (viii) स्मार्ट मीटर एवं प्रबंधन
 - (ix) स्मार्ट पार्किंग
 - (x) कौशल विकास केन्द्र
 - (xi) जल गुणवत्ता अनुश्रवण
 - (xii) अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास
 - (xiii) कुल यातायात प्रबंधन
 - (xiv) व्यापार सुविधा केन्द्र

TABLE - 1

ROHTAS DISTRICT: BLOCK WISE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Sl.No.	Name of C.D. Block	Primary School	Middle Schools	High School	College	Other Inst.
1.	Sasaram	77	20	6	10	10
2.	Dehri	95	18	5	1	5
3.	Bikramganj	102	14	4	2	6
4.	Tilauthu	62	10	3	2	6
5.	Rohtas	56	17	4	1	2
6.	Nauhata	48	13	2	1	2
7.	Sivsagar	47	12	3	3	2
8.	Chenari	98	20	6	2	2
9.	Kargahar	63	14	5	4	2
10.	Kochas	54	11	4	3	2
11.	Dinara	64	13	4	2	6
12.	Dawath	79	15	5	1	1
13.	Surjpura	75	17	7	1	2
14.	Rajpur	87	19	9	2	4
15.	Nasriganj	74	216	4	1	11
16.	Karakat	73	18	6	2	4
17.	Akorigol	70	19	5	2	8
18.	Nokha	56	16	3	1	4
19.	Sanjhauli	60	17	4	1	5

Computed by author on the basis of the district census(Rohtas) 1981,1991&2001.

*college includes private affiliated and training college

** Other include privately managed schools also

** Source: Office of Registrar VKSU, Ara

स्मार्ट शहर के प्रमुख तत्त्व

- (i) क्षेत्र आधारित विकास के निहित भू उपयोग का प्रोन्नयन
- (ii) आवास
- (iii) चलने योग्य वस्ती का सृजन
- (iv) खले स्थान को संरक्षित एवं विकसित करना
- (v) नागरिक मित्रवत एवं लागत प्रभाव शासन व्यवस्था।

स्मार्ट शहर का वित्तियन :-

स्मार्ट शहर मिशन केन्द्र प्रयोजित योजना के रूप में परिचालित की जाएगी, जिसके लिए केन्द्र सरकार प्रति शहर औसतन 100 करोड़ प्रतिवर्ष के आधार पर पाँच वर्ष के भीतर कुल 48000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएगी। बराबरी के आधार पर इतनी ही राशी राज्य सरकार/शहरी विकास द्वारा स्मार्ट शहरों को विकास पर खर्च की जाएगी। इस प्रकार इस मिशन पर कुल 98000 करोड़ खर्च होगा।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रारा निधियाँ परियोजन की कुल लागत का एक हिस्सा होगी।

निष्कर्ष (Conclusion) :-

बेहतर के साथ स्मार्ट सिटी मिशन भले ही दिखाई देता हो लेकिन व्यावहारिक धरातर पर (JNNURM) Mission से इतर नहीं होती। इस मिशन का वित्तियन धरातल ढाँचा जो प्रस्तावित किया गया है, उसे समझने लायक कर्मचारी एवं अधिकारी कम से कम स्थानिय निकायों के पास नहीं है। दूसरा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित निकायों पर यथा BSNL MNTL, जलनिगम इत्यादि पर स्थानिय नगर निकायों का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

तीसरा – ठेका पद्धति से कार्य आवंटन में स्थानीय निकायों की दखलदांजी से कार्य गुणवत्ता प्रभावित होगी।

चौथा – मिशन के सफलता/असफलता के मूल्यांकन हेतु कोई मापदण्ड (Norms) नहीं स्थापित है।

स्मार्ट सिटी मिशन का पहला लगभग पूरा हो गया है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए (100) शहरों में से (98) का चयन किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन की व्यवहार्यता को समय तथा संशोधन की कसौटी पर परख जाना है। चयनित शहरों का जो भौगोलिक रूपरेखा है, उससे एक छोटा सा भाग ही व्यवस्थित है। भू-अधिग्राहण की संभाव्य कठिनाईयों के कारण शहर विस्तार की संभावना सीमित है।

REFERENCES

1. Abrams, C., *Urban Land problems and policies; Housing Town and country planning, bulletin 7, UNO, 1953.*
2. Abrams, P. and Wrigley, E.A. (eds.), *Towns in societies, Cambridge university press.*
3. Achta Rao, T.N, *The concept of Twin Towns, Geographical Review of India, 1967, Vol. 29, pp 104 – 107.*
4. Ahmad, E; *origin and Evaluation of Town of the Uttar Pradesh; Geographical outlook, 1956, Vol.1. pp. 38-58.*
5. Ahmad, S; *'Dacca; A study in urban History and Development', Curzon press, London, 1950.*

6. *Anderson, M.(1971) Family Life in Nineteenth One-story Lancashire, Cambridge University Press.*